Order, order. We will now take up the next item.

Shri S. M. Banerjee: I have already given you a Resolution. Will you give your ruling on that? The argument is that since there is no motion before the House, so it cannot be suspended. Taking advantage of it—I wanted to fill up the vacuum—I gave you the Resolution.... (*Interruption*).

Mr. Speaker: How can that be done? We now take up the other business.

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): I want to move my motion.

Shri Bhagwat Jha Azad: There is a motion on the Order Paper; that ought to be allowed to be moved. We had asked the consent for moving the motion to suspend rule 30. There is a motion to suspend rule 30(2). That should be allowed to be moved.

Shri M. L. Dwivedi: I want to move this motion . . .

Mr. Speaker: That can only be moved if the first one is carried. Unless the first one is carried, how can the second one come in?

Shri Bhagwat Jha Azad: There is no question of first one being carried. Some of the Members hold that it is by the suspension of rule 30(2) only that it serves the purpose. That only comes when Mr. Tiwary does not move the original motion. But a Member who has given the motion wants to move that. You allow this motion to be moved. Let that be moved.

Mr. Speaker: Which one does he want to move?

Shri Hari Vishnu Kamath: Once it is adjourned *sine die*, it is not before the House.

Mr. Speaker: Which one does he want to move?

Shri M. L. Dwivedi: I want to move this motion.

Shri Bhagwat Jha Azad: It is in the Order Paper.

Mr. Speaker: Which one? This confusion should be avoided. Let me understand it.

Shri M. L. Dwivedi: Item 15 of the Order Paper:

> "That rule 30(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha be suspended in its application to the Resolution regarding India quitting the Commonwealth moved by Shri Bhagwat Jha Azad on the 24th September, 1965, further debate on which was adjourned on the 12th November, 1965."

I want to move this motion.

Mr. Speaker: What did Mr. Tiwary do?

Shri M. L. Dwivedi: He said rule 30. He moved something different. I want to move the motion which is on the Order Paper.

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, ठीक है । यह मूव हो गया ।

It is held over till Monday. We now take up the other business. Shri Krishna Deo Tripathi—he is absent. Then, Shri Raghunath Singh.

15.27 hrs.

RESOLUTION *RE.* MODERNISATION OF INDIAN NAVY

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

> "This House is of opinion that immediate steps be taken to develop and modernise Indian Navy in order to make it effective."

मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता कि यह संकल्प सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है । सुरक्षा की दृष्टि से इस-

[श्री रघुनाथ सिंह]

वास्ते आवश्यक है कि हिन्दुस्तान की 3500 मील लम्बी सामुद्रिक सीमा है जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय नेवी के ऊपर है । इस भूमंडल में करीब 70 फी सदी जमीन केवल समुद्र से छाई हुई है । इस 70 फी सदी जमीन में, जो कि समुद्र से छाई हुई है, केवल एक ही सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है, और वह सुरक्षा व्यवस्था है नेवी के द्वारा ।

इस संकल्प के दो पहलू हैं । पहला पहलू तो यह है कि भारत के समुद्र तट की रक्षा की जाये, बन्दरगाहों की रक्षा की जाये और दूसरा पहलू यह है कि जो हमारा विदेशों से व्यापार होता है उस व्यापार की रक्षा युद्ध के समय की जाये ।

15.28 hrs.

[SHRI P. K. DEO *in the Chair*]

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Let us all congratulate the new Chairman on hie elevation. हार्दिक बधाई ।

श्री रघुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में करीब 180 बन्दरगाह हैं जिन में से 7 मेजर पोर्ट हैं, तीन मेजर पोर्ट्स की योजना है, 20 इंटरमीडिअरी पोर्ट्स हैं और 150 माइनर पोर्ट्स हैं । इन पोर्ट्स की रक्षा का भार किस के ऊपर है । पोर्टों की रक्षा का भार केवल भारतीय नेवी के ऊपर ही हो सकता है ।

दूसरे, जैसा मैं ने कहा, व्यापारिक रेखा है । इस व्यापारिक रेखा की रक्षा का भार भी भारतीय नेवी पर है क्योंकि भारत का 88 प्रतिशत व्यापार जहाजों क द्वारा होता है । केवल आधा प्रतिशत हिन्दुस्तान का व्यापार हवाई जहाज या भूमि के द्वारा होता है । इस 477 लाख टन सामान का आयात और निर्यात केवल जहाजों के द्वारा होता है । उसकी कीमत करीब करीब 21 अरब रुपये की लागत की होती है ।

इस समय भारत की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया है । इस दुनिया में इण्डियन ओशन ही एक ऐसा समुद्र है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है । प्राचीन काल से इस इण्डियन ओशन पर भारत में जो भी सत्ता रही उसने अपना अधिकार रखने का प्रयत्न किया है । लेकिन आज इंडोनेशिया, पाकिस्तान और चाइना की जो गुटबन्दी हुई है उसके कारण भारत की समर नीति में आमूल परिवर्तन हो गया है । मैं आपको यह बतलाऊं कि जिस दिन राष्ट्रपति के यहां पदवीदान समारोह हुआ था उस दिन मैं बड़ी उत्सुकता से देख रहा था कि शायद कोई नेवी का भी अफसर हो जिसको कोई पदवी दी गई हो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नेवी के किसी अफसर को कोई पदवी नहीं दी गई । इस का अर्थ यह है कि हमारी नैवी ने इस बार कोई भी काम नहीं किया । अगर हमारे पास नेवी होती तो पाकिस्तान ने साढ़े दस करोड़ रुपये का जो सामान इम्पाउन्ड किया है उस को हम इम्पाउंड करने नहीं देते । आज ब्रह्मपुत्र में छः छः जहाज रुके हुए हैं, हमारे पास नैवी होती तो हम उस को रोक सकते थे । अगर हमारे पास मजबूत नेवी होती तो ईरान और टर्की से सामान आने की पाकिस्तान में जो बात होती है, दूसरे देशों से सामान आने की जो बात होती है हम उस को रोक सकते थे । हम पाकिस्तान का ब्लाकेड कर सकते थे । हम उस की नाकेबन्दी कर सकते थे । लेकिन आज हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है । अमेरीका और ब्रिटेन मारीशश के पास नौसैनिक अड्डे बनाने जा रहे हैं । अदन में अड्डा मौजूद है, सिंगापुर में अड्डा मौजूद है, कराची में अड्डा मौजूद है, चटगांव में अड्डा मौजूद है, इस प्रकार से आप देखें हिन्दुस्तान की सीमा पर विदेशी अड्डे आज मौजूद हैं जहां उन की नेवी है

जहां उन के जहाज हैं। हम चारों ओर से जहां तक कि सामुद्रिक सीमा का सम्बन्ध है घिर गए हैं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपनी नीतियों में आमूल परिवर्तन करना चाहिए।

ऋग्वेदिक काल से ले कर आज तक का इतिहास मैं आप के सामने रखूं। ऋग्वेद में कही सुन्दर चर्चा आती है कि हमें समुद्र के पार ले जाओ, हमें सामुद्रिक शक्ति दो। ऋग्वेद से लेकर के फिर उस के बाद चाणक्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में क्या कहा है, उस को देखें, उस ने कहा कि हमें नेवी पर जोर देना चाहिए क्योंकि नेवी के ही द्वारा किसी विदेशी देश से हमारा कोई सम्पर्क हो सकता है। उस के बाद मौर्य काल में देखें। सिकन्दर, अलेग्जेन्डर दि ग्रेट आया। उस के साथियों ने भारतीय नेवी की भूरि भूरि प्रशंसा की है। उन्हों ने कहा है भारतीय नेवी हिन्दुस्तान की एक बड़ी अच्छी नेवी है। इस के बाद 25 बी. सी. में पाड्य राज के लोग रोम के सम्राट अगस्टस सीजर के समारोह में शामिल हुए। हमारी नैवी वहां भी पहुंची। फिर गुप्तकाल आता है उस वक्त भी हमारे पास काफी नेवी थी। दसवीं शताब्दी में चोल राज ने बंगाल की एक खाड़ी को एक झील की तरह बना लिया था। भारतीय महासागर में जितने टापू थे, बंगाल की खाड़ी में जितने टापू थे उन पर चोल राज की नैवी का एकमात्र अधिकार था। इसी प्रकार से पन्द्रहवीं शताब्दी में 90 वर्ष तक भारतीय नेवी ने पुर्तगाली नेवी को हराया और 1590 से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक के अन्त तक जमोरिन ने, कालीकट में, पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगालों को नहीं आने दिया। इस के पश्चात् कुंजली तृतीय के काल में 40 वर्ष तक उन्हों ने पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा की अपने यहां बने हुए जहाजों से अपने सैनिकों से।

इसी प्रकार से आप देखें। अकबर के समय में बंगाल की खाड़ी में 3 हजार सैनिक जहाज थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस वक्त चाहे पुर्तगीज हों, चाहे अंग्रेज हों, चाहे डच हों, कि हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठा कर देख नहीं सकें।

एक सदस्य : और नेहरू काल में क्या हुआ ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं आता हूं उसी तरफ।

इस के बाद शिवाजी महाराज का काल आता है। 25 वर्ष तक शिवाजी महाराज ने माहबी से ले कर मलाबार तक समुद्र तट की रक्षा के लिए हिन्दुस्तानी नेवी को रखा ताकि कोई भी विदेशी शक्ति हिन्दुस्तान में न आने पाये। फिर 1698 में कन्नोजी आंग्रे ने बम्बई से विगुल तक अपनी नेवी के द्वारा भारतीय तट की रक्षा की और जो हमारी भारतीय नेवी की गौरव पताका है, उसको वह फहराते रहे। फिर 1729 में भी कन्नोजी के देहान्त के पश्चात् सम्भाजी आंग्रे हमारी भारतीय नैवी की गौरव पताका को फहराते रहे। 1750 तक आप इस प्रकार देख जायें, तुलाजी के समय तक हमारी नेवी किसी भी विदेशी शक्ति के सामने हारी नहीं। 1750 में तुलाजी ने अंग्रेजों के विजिलेंट जहाज को जिस पर पचास पचास, साठ साठ तोपें थी, उन को हराया।

फिर इस के पश्चात् भारतीय इतिहास अंधकारमय हो जाता है। भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और साथ ही साथ भारतीय नेवी भी सो जाती है।

इस के बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हम लोगों ने इस बात की कोशिश की कि हमारी नेवी बने। लेकिन अगर आप बजट देखें, जो भी बजट सन् 1947 से ले कर के अब तक यहां पर रखा गया, मुश्किल से उस में से 2 परसेंट बजट का भारतीय नेवी के ऊपर रखा गया है। आज आप देखें,

[श्री रघुनाथ सिंह]

चीन की शक्ति को देखें, इन्डोनेशिया और पाकिस्तान को देखें। मैं सिर्फ एक चीज को लेना चाहता हूं, सबमेरिन को। चीन के पास 30 सबमेरिन हैं, इन्डोनेशिया के पास 6 और पाकिस्तान के पास 1 सबमेरिन है। इस प्रकार से हमारे जो कि विरोधी हैं, उन के पास 37 सबमेरिन हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : किस ने दिया उन को ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं आता हूं उस पर। लेकिन हमारे पास एक भी नहीं है। कामत साहब ने पूछा है कि उन को किस ने दिया है। चाइना के पास जो 30 सबमेरिन हैं इन को सोवियट रशा ने दिया। इन्डोनेशिया के पास 6 सबमेरिन हैं, इन को सोवियट ने दिया और पाकिस्तान के पास एक सबमेरिन है, उस को यू० एस० ए० ने दिया। हम को किसी ने नहीं दिया।

चाहे हमारी जो भी नीति रही हो, हम आजादी के पश्चात् अपनी नेवी में कोई तरक्की नहीं कर सके। आज वह समय आया है कि यू०एस०ए० ने पोलोरिस सबमेरिन और न्यूकिलियर सबमेरिन, मिजाइल से फिटिड सबमेरिन तैयार की हैं। यू०एस०एस० आर० के पास 30 न्यूकिलयर पावर सबमेरिन हैं, 19 मिजाइल सबमेरिन यू०एस० एस० आर० के पास हैं और दस सबमेरिन प्रति वर्ष बनाने की योजना आज सोवियत की है। इसी प्रकार से यू०एस०ए० की योजना है कि 1967 तक 51 न्यूकिलअर पावर की फ्लीट उन के पास हो जाय। हमारे पास क्या है ? हमारे पास नाम मात्र की नेवी है। आप देखें .....

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं। इतने बड़े नेता बोल रहे हैं, सदन में गणपूर्ति नहीं है

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिये घंटी बज रही है ....

श्री रघुनाथ सिंह : अब मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी ...

सभापति महोदय : नो, देयर इज नो कोरम सो फार। ... देअर इज कोरम नाउ।

श्री रघुनाथ सिंह : अब मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि चीन के पास 830 यूनिट जहाज हैं, जिस में से 80 प्रतिशत सिर्फ सोवियट रशा ने दिया है। इंडोनेशिया के पास 207 यूनिट है, उस के पास जितनी नेवी है वह सब नेवी सोवियट रशा की दी हुई है। पाकिस्तान के पास 30 यूनिट हैं। उस के पास जितनी नेवी है उस में करीब करीब 90 प्रतिशत अंग्रेजों की, यू०के० की दी हुई है और करीब दस प्रतिशत जिस में कि एक सबमेरिन भी है, अमेरिका ने दी है। इस प्रकार यह तीनों शक्तियां एकांगी नहीं हैं, इन के पास यू०एस०एस०आर० की टक्नीक मौजूद है, यू० के० की टैक्नीक मौजूद है और अमेरिका की भी टैक्नीक मौजूद है। तीन जगह टैक्नीक हैं। उन के हथियार, उन के पास मौजूद हैं। हमारे पास क्या है ? हमारे पास सिर्फ अंग्रेजों ने जो कुछ हमें समुद्री ताकत दी है वही हमारे पास है। इस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है।

चीन ने करीब पन्द्रह वर्षों के अन्दर अपने यहां शिपयार्ड बंधाई, कैन्टन और एक रिपब्लिक शिपयार्ड बनाया है। उन्होंने अपनी नेवी बनायी। तीन शिपयार्ड उन के अपने हैं। उन के यहां टारपीडो फ्लीट है। यह सब वह अपने यहां बना रहे हैं। आज वह रूस के ऊपर मनहसिर नहीं है। रूस अगर उन को सहायता न दे तो भी अकेले वह लड़ने के वास्ते तैयार हैं। क्योंकि उन्होंने अपने तीनों शिपयार्डों का अच्छी तरह से विकास कर लिया है।

जहां तक पर्सोनल का सम्बन्ध है, चाइना के पास, 1,24,000 सामुद्रिक अफसर और सैनिक हैं, इंडोनेशिया के पास 34,000 और पाकिस्तान के पास 8,250 सामुद्रिक अफसर और सैनिक हैं। इस प्रकार इन तीनों देशों के पास कुल मिला कर 1,66,250 सामुद्रिक अफसर और सैनिक हैं। इस के मुकाबले में हिन्दुस्तान के पास केवल 19,500 नाविक सैनिक हैं। अगर हमारी नैवी को इन तीनों शक्तियों की नैवी के साथ कम्पेयर किया जाये, तो वह उस की दो परसेंट भी नहीं होगी।

इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम को अपने गार्डनरीच और मैजागांव डाकयार्डज् को विकसित करना चाहिए। वहां पर छोटे छोटे जहाज बनाने चाहियें। हम ने यू० के० के साथ फिगट बनाने के सम्बन्ध में एक समझौता किया। उस समझौते को हुए दो बरस हो गए हैं, लेकिन हम यू० के० के साथ मिल कर कोई फ्रिगेट या कोई अन्य सैनिक जहाज बनाने में सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हम को अमरीका या ब्रिटेन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जैसे हम ने जैट हवाई जहाजों के लिए अपना टैकनीक बनाया है, वैसे ही अपनी नैवी को सुसज्जित करने के लिये हमें स्वयं अपना टैकनीक बनाना चाहिए।

आप को यह जान कर गर्व होगा कि मेजागांव एशिया का सब से पुराना डाकयार्ड है। यह 1673 से काम करता रहा है। और 24 अप्रैल, 1771 को अंग्रेजों ने पहले पहल यहां से जहाज बनवाना शरू किया। उस के बाद इस ने इतनी तरक्की की कि 1800 में अंग्रेजों ने इस से 56 तोपों का कार्नवालिस फ्रिगेट बनवाया। सन् 1802 में 800 टन का जहाज पिट वहां पर बना, जिस पर 74 तोपें लगी थीं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम पूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है—अब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री रघुनाथ सिंह : सन् 1812 में 1200 टन का एक जहाज इस शिपयार्ड में बना, जिसका नाम वाल्मर्स दि ग्रेट था। वहां पर 12 अक्तूबर, 1817 को जिस जहाज का जलावतरण हुआ, वह हिन्दुस्तान का जहाज आज विश्व का सब से पुराना जहाज है और आज भी समुद्र पर तैर रहा है। इस जहाज का नाम फ्रीडान्ट है। 148 बरस के पश्चात भी आज यह जहाज यू० के० की बन्दरगाह में मौजूद है और उसके गौरव का एक निशान है, चिह्न है। लेकिन कितने लोग यह जानते हैं कि जिसको यू० के० वाले अपना जहाज कहते हैं, वह हिन्दुस्तान में बना था। आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि 1954 में जब उस जहाज पर रंगाई की जा रही थी, तो 137 वर्ष के पश्चात उस पर केवल दो चपड़े निकले। इसके अतिरिक्त लार्ड नेल्सन का फ्लैगशिप विक्टरी हिन्दुस्तान में ही बना था।

15·45 hrs.

[SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA *in the Chair*]

हम उस समय एक बहुत बड़ी जहाजी शक्ति थे। लेकिन आज हमारी वह शक्ति दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। हम ने उस की तरफ़ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है।

मेरा निवेदन यह है कि हम लोग एटामिक पावर से न घबरायें, बल्कि हमको एटामिक पावर का प्रयोग करना चाहिये। अपनी नेवी, नौशक्ति, को बढ़ाने के लिए हम एटामिक पावर का प्रयोग करें। हम अपने यहां एटामिक मिसाइल्ज से गठित जहाज बनाने की कोशिश करें। आज कल दुनिया में पोलरिस और नाटिलस जैसी सब मैरिन्ज प्रचलित हैं,

[श्री रघुनाथ सिंह]

जो तीस तीस घंटे तक पानी के नीचे रहती है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है—अब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक जहाज बनाने का ताल्लुक है, आज स्वीडन ने जहाज निर्माण में विशेषता प्राप्त कर ली है। जापान भी स्वीडन से जहाज खरीद रहा है। जापान ने अपनी नेवी को तो हजार टन के फ्रिगेट से सुसज्जित किया है, जिस की रफ्तार चालीस नाट प्रति-घंटा है । इसी प्रकार हम लोग भी अपने डाकयार्ड में ऐसे जहाज बनायें, जिनकी रफ्तार तेज हो और जो आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हों ।

बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मेन कम्पनी ने गवर्नमेंट से प्रार्थना की कि वह डीजल इंजिन बाहर से इम्पोर्ट करती है, उन को 150 लाख रुपये का फ़ारेन एक्सचेंज दिया जाये, तो इस देश के जहाजों के लिये इंजिन बनायें । सरकार ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसने तीन बरस में छः करोड़ रुपये इंजिन खरीदने के लिये फ़ारेन कम्पनियों को फ़ारेन एक्सचेंज में दिये । हमारी नेवी का विकास करने के लिये एक सुनिश्चित योजना होनी चाहिये । नेवी में सब से इम्पार्टेंट चीज इंजिन है । हमारे देश में किर्लोस्कर का बड़ा अच्छा कारखाना है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह किर्लोस्कर को कहें कि वह हमारे जहाजों के लिये अच्छे से अच्छे इंजिन बना कर दें ।

अगर सरकार को शिपयार्ड खोलना हो, तो इस के लिए कारवार बड़ी अच्छी जगह है। भंडारा में सरकार ने आधुनिक शस्त्रों का कारखाना खोला है । इसी प्रकार नेवी में जिन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हो, उन के लिए भी कारखाना खोला जाना चाहिए । जिस प्रकार सरकार ने नैट हवाई जहाज बनाया है, उसी प्रकार अपने टेकनीक से उसे स्ट्राइकिंग पॉवर का निर्माण करने के उद्देश्य से हल्के क्रूजर, सबमैरिन और फ्रिगेट बनाना परमावश्यक है ।

चीन के पास 830, इंडोनेशिया के पास 207 और पाकिस्तान के पास 30 यूनिट जहाज हैं । इस प्रकार इन तीन शक्तियों के गुट के पास कुल 1067 यूनिट जहाज है, जब कि हिन्दुस्तान के पास सिर्फ 55 यूनिट जहाज हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 3500 मील की जो हमारी समुद्री सीमा है, इसकी रक्षा के लिए यह परमावश्यक है कि हमारे पास एक सुदृढ़ नेवी हो । हमको अपनी यह पालिसी घोषित करनी चाहिये अपनी यह नीति घोषित करनी चाहिये कि भारतीय महासागर में भारत सरकार का इनफ्लुएंस होगा । वह हमारे सफीयर आफ इनफ्लुएंस में होगा । और जो विदेशी शक्तियां यह सोचती हैं कि भारतीय सागर में आकर वे सैनिक अड्डे खोल सकती हैं उनको यह भी सोचना होगा कि किस के खिलाफ ये अड्डे होंगे । वह सैनिक अड्डा हिन्दुस्तान के खिलाफ होगा । अमरीका कहा करता था, यू० के० कहा करता था कि वे जो पाकिस्तान को सहायता दे रहे हैं उस सहायता का हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हमने देख लिया है । उसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है । वह सहायता हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है । जिस प्रकार से इंग्लैंड और अमरीका द्वारा दी हुई सहायता का हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है उसी प्रकार से ये जो सैनिक अड्डे हिन्द महासागर में खोलने का प्रयास किया जा रहा है ये सिर्फ विडम्बना मात्र हैं, जाल मात्र हैं और इस विडम्बना में हमें नहीं फंसना

चाहिये । कोई भी ब्लैट क्यों न हो जो यह कहती है कि वह हिन्द महासागर में आना चाहती है, तो उसका हमें घोर विरोध करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपके सम्मुख उपस्थित करता हूं । और आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा । जव्हाण साहब ने, उनकी सेना ने जैसी वीरता स्थल शक्ति में और नभ शक्ति में दिखाई है, ऐसी ही वीरता वे जल शक्ति में भी दिखायें और पाकिस्तान की नाकेबन्दी करके उसको दिखा दें कि हमारी नौसेना भी मजबूत है ठोस है । पाकिस्तान को आप कैसे पंगु कर सकते हैं, कैसे आप ईस्ट और वैस्ट पाकिस्तान को डिवाइड कर सकते हैं । केवल नौसेना के द्वारा ही कर सकते हैं । हवाई जहाजों से उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं । वैस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को सहायता सिर्फ जहाजों के द्वारा ही भेज सकता है । इसलिए आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिये कि आप उसको रोक सकें । और पाकिस्तान हमारे खिलाफ युद्ध करता है तो उसका ब्लाकेड किया जा सकता है । फिर टर्की या ईरान या किसी और देश में शक्ति नहीं हो सकती है कि आपके खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करे ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं ।

Mr. Chairman: Resolution moved:

"This House is of opinion that immediate steps be taken to develop and modernise Indian Navy in order to make it effective".

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): I beg to move:

"That for the original Resolution, the following be substituted, namely:—

'This House calls upon the Government to appoint a Committee immediately to suggest ways and means for developing and modernising Indian Navy so that it may be in a position of playing an effective role in any emergency with instructions to report within three months".

Mr. Chairman: Both the original Resolution and the substitute Resolution by way of amendment are before the House.

श्री जीनारायण दास : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव हमारे मित्र श्री रघुनाथ सिंह जी ने रखा है उसका न केवल मैं बल्कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य हृदय से समर्थन करेंगे ऐसे मेरी आशा है इस में कोई शक नहीं है कि जो प्रस्ताव उनका है उसका सरकार भी विरोध नहीं कर सकती है । पाकिस्तान और चीन ने हमारी सीमाओं पर जो रुख अख्तयार किया है उससे इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिये कि हमको अपनी तीनों प्रकार की जो सेनायें हैं थल सेना, जल सेना, और नभ सेना उन तीनों को हर तरह से सुसज्जित करना होगा तीनों को मजबूत बनाना होगा ताकि किसी को भी हमारी सीमाओं का न थल में, न जल में, और न नभ में किसी भी प्रकार से अतिक्रमण करने का दुस्साहस हो ।

विदेशी मामलों में हमने यह रुख अख्तयार किया है कि किसी भी ब्लाक में हम नहीं जायेंगे । जब हमने यह रुख अख्तयार किया था उसी समय हमें यह भी सोचना चाहिये था कि ऐसा रुख अख्तयार करके हमने देश के सामने एक ऐसा प्रश्न उपस्थित किया है कि हम स्वयं हर क्षेत्र में, नभ में, जल में और थल में मजबूत नहीं रहेंगे तो ऐसी हालत में हमारे ऊपर किसी भी समय आफत आ सकती है । लेकिन देर से ही सही, हमारे सुरक्षा मंत्री मैं समझता हूं कि चाहे हम प्रस्ताव पास करें या न करें, सभी क्षेत्रों में सेनाओं को

[श्री श्रीनारायण दास]

मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी बताया है हमारी जो जल सेना है उसका विकास जितना होना चाहिये था अब तक चाहे कुछ भी कारण रहा हो, नहीं हो सका है। अब समय आ गया है कि हमें इस बात की पूरी जानकारी हो कि हम किस तरह से अपनी जल सेना को मजबूत बना सकते हैं और कैसे उसको नये से नये जाहजों से, नये से नये अस्त्र शस्त्रों से सुसज्ज कर सकते हैं किस तरह से उसका विकास कर सकते हैं।

मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। इस प्रश्न के महत्व से कोई भी माननीय सदस्य या सरकार इंकार नहीं कर सकती है। सभी मानेंगे कि इसके विकास की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां इस प्रस्ताव के मूल सिद्धान्त को हम मानते हैं वहां यह भी जरूरी है कि हर पहलू से किस प्रकार हम इसका विकास कर सकते हैं आधुनिक ढंग से किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इस बात के लिये विशेषज्ञों की राय की जरूरत है। इसलिये मैंने एक संशोधन इस प्रस्ताव में उपस्तिथ किया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय विशेषज्ञों की एक कमेटी की नियुक्ति करें जो हर पहलू से इस बात पर विचार करे। इस में कोई संदेह नहीं है कि उसका विकास करना हमारा काम है। लेकिन जब तक हम विशेषज्ञों की राय ले कर इस संबंध में इनके विचार न जान लें तब तक हैपहैजर्ड वे में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और न ही हमें बढ़ना चाहिये। इस तरह से अगर आप विकास के काम को करते रहेंगे तो यह मुनासिब नहीं होगा। इसलिये मैं कहता हूं कि एक कमेटी सरकार नियुक्त करे जो ३ महीने के अंदर अंदर उपाय बताये कि किस तारिके से हम अपनी जल सेना को मजबूत बना सकते हैं और आधुनिक से अधिक आधुनिक तारीके से किस तरह उसका विकास कर सकते हैं।

इस शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को सदन के सामने उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेगें।

Shri P. K. Deo: (Kalahandi): Mr. Chairman there can be no two opinions that this country with its maritime past and with its glorious record of maritime history could have a very well equipped navy. I entirely agree with the hon. Mover, Shri Raghunath Singh, that a visit to any South-east Asian country would convince anyone about the extent to which our cultural and commercial contacts spread to those distant lands.

Those who were destined to rule this country made this blunder of not having a very well-equipped navy. Though the entire Indian Ocean was exposed to the piracies of the Portuguese, the British, the French and the Spaniards, still they never cared to have a very good navy. Rather they expected that the danger would be coming from the north-west.

The complexion of the situation has now completely changed. Our northern border is now more vulnerable than the sea-coast, with neighbours like Pakistan and China. I do not think that in going ahead with streamlining our navy, we should neglect our army and the air force which are all the more important for the purpose of guarding our northern border.

15·59 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

It is very important that we must have a very capable navy. Pakistan

got a submarine for a certain purpose, for training and so on. But we are very sorry to learn that it is being used for aggressive designs against this country. The Pakistani press had been boasting that its one single submarine completely paralysed our navy. While I am not prepared to believe those claims, at the same time we also want to have our own submarines fitted with the latest gadgets like Polaris or other powerful missiles.

16 hrs.

I quite agree that the dockyards at Mazgoan and Garden Reach should be streamlined, and the shipbuilding yard at Vishakapatnam should be improved, so that we can build our own frigates and improve the tonnage of the Indian Navy. At the same time, we should not over-emphasize this point and say that the defence of the Indian Ocean is the concern of the Indian Government. It is not. Our territorial waters extend only three miles or six miles, I am not sure. But the installation of the British defence establishment in the Chagos Islands has created a good deal of indignation and anger in this country, and I associate myself with those sentiments.

Sir, I feel that to have a very efficient Navy, we should make our people more sea-minded, so that more naval wings of NCC should be started in the various schools established in the maritime States. It is no use starting such schools in the Punjab or Madhya Pradesh which are landlocked. In maritime States like West Bengal, Orissa Andhra Pradesh, Madras or Kerala and others we must start in schools the naval wing of NCC and that will create a liking in the minds of the boys to go in for the Navy.

My remarks in this regard will not be complete unless I mention the strategic importance of some of our islands like the Andamans. If you look at the map, the Great Nicobar Island is only 70 miles from the northern tip of Sumatra, and Indonesia has been equipped with Russian submarines.

The entire situation in Indonesia is now in the melting pot, and we do not know whether the PKI (The Communist Party of Indonesia) or the army is going to come up, but I must say that the way Indonesia behaved in the Indo-Pakistan conflict rather surprised us. We had been a very good friend of Indonesia all along in her conflict against imperialist Powers. We had been giving all support. India went all out, but at the time of trial, Indonesia completely betrayed us. So, we should not lose sight of Indonesia on the one side and Pakistan on the other side.

It has been brought to my knowledge that one naval establishment has been established at Port Blair, that is NS Jarawa. I do not think that it has been properly manned or has been manned by sufficient number of staff. I expect that our naval post at the farthest end of India should be very well equipped. In season and out of season we find that Chinese fishing boats come and fish in our territorial waters near Andamans, and we have not got fast enough ships which could chase them and catch hold of them. The other day a fishing boat from Taipeh was caught and it was left at Port Blair. So, all these things have to be considered. If INS Jarawa is to function effectively, we must have a well-equipped naval establishment in the Andamans.

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Sharada Mukerjee. Each Member to take five or six minutes. The time allotted is only 1½ hours.

Shrimati Sharada Mukerjee (Ratnagiri): I would like to congratulate Shri Raghunath Singh on having brought up this resolution.

It is surprising how little has been discussed about the Navy in the House. Some time ago I met a naval officer, and while other officers were talking of the nuisance of M.P's' questions, the naval officer there said, "We do not have to worry, we are at sea." The fact is we are also at sea about them. Nobody has thought about it,

[Shrimati Sharda Mukerjee]

nobody has really discussed it. So Shri Raghunnath Singh has to be congratulated.

Before I go on to the modernisation etc., which is a very expensive process and has to fit in with our capacity to finance the Navy, Air Force and Army in the order of priorities, I would like to stress one-thing which can be, I think, achieved without much expense. Since 1947, though there has been a complete rethinking in the other services, I am sorry to notice that there has been very little rethinking in the Navy. Even today, when exercises are carried out, they are carried out in liaison with the British Navy in the Mediterranean etc. It is the same thing with regard to training, with regard to equipment and even with regard to the officers uniforms. In the Army and Air Force at least, after independence the uniforms have been remodelled and changed to suit Indian conditions, but in the Navy they still wear what is called the monkey jacket. It is a little coat like a little jacket, and very tight trousers, and this is the uniform of the Royal Navy. In 17 years if the Navy has not advanced to the extent where even the uniforms of the officers have not been remodelled, you can imagine how little rethinking has been done in the matter of other things.

We should have today the same kind of planning in the Navy as we are having in the Army and Air Force, and the policy of non-alignment etc., which we follow must be reflected in the planning of the Navy. Therefore, I would request the Minister that even if the modernisation process is expensive, he might consider at least the procurement of ships etc., not only from Britain.

We know to our cost that some years ago we were landed with an aircraft carrier, the tropicalisation of which has cost us more than the purchase of a new aircraft carrier would have. Not only that. With only one air craft carrier for the entire sea coast, it is not going to be much use to us. It has also to have six special type of aircrat. So, the Navy also had to have an air force. The pilots for theese aircraft for the Vikrant could not be taken from the Indian Air Force, but we had to have a separate little air force. It is all right when you have a fleet of aircraft carriers, there you can have special types of aircraft, special types of training etc., but I cannot understand why some of the pilots cannot be seconded from the Indian Air Force to the naval aircraft; because, in any case, what is the duration of a pilot, what is the lifespan during which he can fly? He can fly probably eight or nine years. Then, what happens to him? To what use can he put the experience he has gained? If he is seconded from the Air Force to the Navy, then he can come back to the Air Force and utillise the experience he has had, but that is not to be. The British Navy had an aircraft carrier in the last war and they had certain types of pilots who were used. Therefore, the Indian Navy, having one aircraft carrier, had to follow the British pattern.

So, the first thing that the Navy has to do is to break off from this long and well-established link with the British Navy.

One more point. There should be some kind of a plan whereby the merchant marine can work with the Indian navy if we are in a time of crisis. We cannot afford to have a big enough navy but we can certainly have some plan, some kind of a link between the merchant marine and the Indian navy so that they can function together in trouble. For God's sake, please do not carry on Rule Britania in the Indian Navy; let us have 'Rule India',

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): Mr. Deputy-Speaker, nobody would be happier than I if Mr. Raghunath Singh's very enthusiastic and persistent desire that we should have a big and strong navy could be implemented. The trouble is that we have to deal with realities and we have to function within certain limitations. Our country being as it is, and therefore in the system of priorities it is inevitable that the Army and the Air force have to be given much greater priority than the Navy because eperience has shown that mainly our land borders in the North, east and the west are threatened today rather than the coastlines. Then, apart from the financial limitations, the main limitation in the way of doing whatever is possible within our limited resources is, as Mrs. Sharda Mukerjee pinted out, the inability to change our thinking. Our thinking on the subject has remained, I do not say within a monkey jacket—to use Mrs. Mukerjees expression—but within a strait jacket. After what has happened in August and September, it gives one food for thought. Only last year our Navy had participated in the annual joint Commonwealth naval exercise.

Shri Raghunath Singh: Pakistan also was there.

Shri Indrajit Gupta: The annual report of the defence ministry takes great pride in recounting the fact that seven ships of the Indian Navy and 2500 men participated in these joint exercises with units of the British Navy and the Pakistan Navy. This is the way we are going on. What is the total result of it all? When hostilities broke out, some Pakistani cruiser or destroyer or something sneaks up stealthily to Dwaraka port; bombards it and gets away with impunity and we are not able to do anything. These are our partners with whom we are having joint exercises year after year. This kind of thinking is persisting.

Then, the aircraft carrier, Vikrant, which Mrs. Mukerjee mentioned. Somebody sold us a white elephant at that time. This aircraft carrier is not only expensive to maintain. Everyone knows that it is quite vulnerable; it is the most vulnerable of all vessels, of all targets. Also, regarding the fleet air arm—we call it very grandioquently by the name of fleet air arm—it means planes which are to function from the aircraft carrier. As far as I know the negotiations which we had carried on with the British primarily to get a suitable aircraft for this fleet air arm, the Sea Hawks and other fighters, have not come to the extent to which we had required them and asked for them. I do not know where this is based or how often it sallies forth into the waters of the ocean, but we cannot use it in any case. It is primarily an offensive weapon which is used to strike enemy objectives on a territory where it is not possible to land our army or air force and the aircraft carrier lies alongside in the waters and uses its air arm to bombard objects ashore. We are not carrying out that kind of offensive operation at the moment anywhere. I say that we must get out of the strait jacket of thinking. I would demand that the first thing is, it was the duty of the government to tell us and to assure us after the recent hostilities with Pakistan and the role Britain played in these hostilities that in future joint Commonwealth exercises of a military nature, whether naval or army or any other, would have to be stopped. I think it is a national disgrace that we should continue to participate in these exercises: I hope it will not be done in the future. Secondly, we have made this agreement with the British commercial firms for the manufacture of Leader class frigates in the Mazagaon dock in the year 1967, if that work goes on according to schedule. This morning during the question hour, poor Mr Raghuramaiah was trying to explain to us the fate of all these commercial agreements for military hardware At

[Shri Indrajit Gupta]

the moment orders worth £7 million are outstanding of which orders worth £500,000 have been supplied. Whether the balance will be supplied or not is completely in the dark and nobody knows. Is the Minister of Defence Production in a position to assure all of us that even this limited agreement with Vickers Armstrong to complete this project will actually be carried out as per schedule. It is not within the capacity of Mr. Thomas, I think, to give a firm assurance to this House. Therefore, it is a very serious matter. We have no capacity in this country for making adequate steel plate for the hulls of vessels.

As a result of that even the ordinary civilian vessels to be produced from the Vizag shipyard are lagging behind because we have not got the cpacity for these plates; we have to depend entirely on imports. There is no proper steel plate mill in the country except Rourkela and that does not function properly. In these circumstances what are we to do? We have to concentrate primarily on two things. One is, to develop whatever capacity there is in the country to make small vessels like frigates or torpedo boats and that kind of thing. We cannot go beyond that. And secondly, to acquire whatever vessels we can, whatever the naval experts would like to give priority to, from friendly countries that are prepared to give them to us on favourable terms. I am happy that some agreement has recently been signed with the Soviet government for the supply of sub-marines; we do not know the details about it yet. But we have now passed the stage of cruisers, battle ships; we cannot manufacture them, and they are themselves becoming obsolescent, and we cannot go in for polaris missiles and nuclear missiles, and at the moment nobody will give them to us. Therefore, whatever plans we have for the development of the navy must be realistic and within our limitations.

The first thing is to break with the old type of thinking and get out of this commonwealth-naval-exercises racket which goes on from year to year. Through them I think much of our naval secrets are also divulged, through Britain and by other members, to the Chinese and the Pakistanis. This thing should be stopped. We should develop our own independent capacity for torpedo boats and frigates and that kind of light craft, and also try to get submarines or destroyers—because the destroyers we have are completely obsolete—from countries which are prepared to help us on a friendly basis. That is the only way in which we should proceed.

Shri Ravindra Varma (Thiruvella): Mr. Deputy-Speaker, I support the motion which has been so ably moved by my hon. friend from Varanasi. In fact the House must be indebted to him for the persistent way in which he has been marshalling facts and drawing the attention of the House to the extreme urgency with which the country has to turn to the task of strengthening our Navy. My hon. friend who spoke before me said that our land frontiers are more vulnerable and it has been proved right that we devoted our attention to the building up of our strength to meet aggression on the land frontiers. But a nation cannot ignore any of its frontiers. Vulnerability, whether it is on land or air or sea, is a sign of weakness. After all the facts of geography cannot be wished away by anyone. Our country has got 3500 miles of coastline; and that is something which no one can ignore. Sir, it is again necessary for us to remember that we are living today in times when we do not seek imperial protection or interference. If, in the past, emphasis was laid on the strengthening of our land forces, and in recent days emphasis is being placed the strengthening of our aerial forces, India cannot ignore the fact that the

vulnerability of her seas is increasing, is bound to increase, because of political, international factors. When Britain was responsible for the defence of this sub-continent, Britain could take care of the defence pyramid on the oceans. Singapore was under the British; there was a naval base in Singapore; Aden was under the British. The Cape of Good Hope was protected by the British; all entrances to the Indian Ocean were protected by the British. It is true that India at that time did not have a very big navy to boast of, but there was no doubt that India, which was part of the British possessions, was protected by the strength of the British Navy.

Today, India is free, and we are proud that we are free; but when we are free, we must also take upon ourselves the responsibility that devolves on us as a result of that freedom. It is not possible for us to hope that the naval base of ritain will rest for all time at Singapore. We do not want that to happen. We do not think that the people of Aden must be denied their legitimate aspirations for freedom. We know that South Africa today is a hostile country, Who then will guard the gates and plug the loopholes in the Indian Ocean? Who will see that the Indian Ocean is not exposed to anemy naval action? Who then will take the responsibility for protecting the coastline of our country? Unless, therefore, even at this hour, we turn our attention to the necessity, consistent with our resources, to build up our navy, we will be ignoring a very important element in our defence which we can ignore only at our peril.

Sir, I do not want to take the time of the House by giving statistics as my hon. friend the Member from Varanasi has done. He has produced an armada of facts and some imaginary details before the House. (*Interruption*). I dellberately used the word, because some of the things that he said will have to be proved, unless history is rewritten in Banaras. But leaving them aside, he said China has 30 submarines; Indonesia has six submarines and Pakistan has one, which has been lent to her for use; perhaps he is unaware of a much more serious development that has taken place. It has been reported that two of these six submarines which the USSR has given to Indonesia are now with Pakistan, that Indonesia, as a result of her decision to help and assist Pakistan in her fight against India, is lending the services of two of her submarines to Pakistan, and they are today under the operational command of Pakistan with mixed crews. I would like the Government to assure the House that sufficient steps are being taken, sufficient measures are being taken, under such circumstances, to increase the strength of our naval forces.

For lack of time, it may not be possible for me to deal elaborately with the measures that have to be taken to strengthen our navy.

My hon. friend, the Member for Ratnagiri and the hon. Member opposite, the Member for Calcutta South West, who spoke before me, referred to the need for free thinking, for a new way of thinking, and the necessity to delink our plans from the plans and projects and programmes of those on whom we cannot depend. It has already been proved that we cannot depend on British assistance for strengthening our navy.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Ravindra Varma: I shall finish in two minutes. It is, therefore necessary for us today to think in terms of securing assistance from every source from which we can get it, from the USSR, from Yugoslavia or from any other country which is in a position to help us with submarines, Destroyers, frigates and aircraft carriers.

Sir, I would refer only to one more important point before I conclude

[Shri Ravindra Varma]

That is again a point which has been referred to briefly and summarily by my hon. friend, the Member for Varanasi, the need to see that we have enough shipyards in this country which will enable us to produce frigates and vessels of the kind which could be used in war and in peace, in defence as well as trade, and in the defence of trade. Here, we could say that the Government does not have much to commend itself to the House. I have only to refer to the sad story of the Cochin shipyard which has been hanging fire for 15 years. 15 years of procrastination, delay, and inefficiency. These years are a monumental testimony to the lethargy, and lack of forethought of the Government in this regard. With such lack of forethought, it would not be possible for us to think in time and take the measures necessary to strengthen our navy. I hope that this lack of forethought will be a thing of the past and that with a new dynamism and dedication we will devote our energies to strengthen our navy so that our seas too may cease to be vulnerable.

श्री बड़े (खारगोन) : मैं अपने मित्र श्री रघुनाथ सिंह जी को इस प्रस्ताव को रखने के लिये हार्दिक बधाई देता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस की ओर उन्होंने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। 18 साल से जब से कांग्रेस के हाथ में भारत के शासन की बागडोर आई है, जो दूरदर्शिता किसी शासनकर्ता में होनी चाहिये, वह दूरदर्शिता उसने प्रदर्शित नहीं की है। जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा जाता है और जब आग लगती है तब फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाती है उससे पहले उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की जाती है। जब पाकिस्तान का और चीन का हमला हुआ तब अपने थल सेना की ओर ज्यादा लक्ष्य किया। तब आपने इसका बजट बनाया। जब चीन का आक्रमण हुआ तब आपने मांउटेनीरिंग डिविजन तैयार किये, उधर आपने खर्च किया। अब अगर पानी की तरफ से शत्रु आता है, समुद्री रास्ते से आता है तो उस पर अधिक खर्च करने की बात हम सोचेंगे।

मैं मजगांव डाक में गया हूं। उसको मैंने देखा है। वह बहुत ही खराब हालत में है। कारण यह है कि शासन वहां पर खर्च करने को तैयार नहीं है । उधर उसने ध्यान ही नहीं दिया है। नेवी के साथ-साथ जितना जाहजों से व्यापार होता है जितना समुद्री रास्ते से व्यापार होता है वह भी फोरन शिप्स से होता है, काफी बड़ा उसका हिस्सा फोरन शिप्स से होता है । वह व्यापार भी सारे का सारा हमारे हाथ में नहीं है। कारण केवल मात्र एक है कि शासन में जो दूरदर्शिता होनी चाहिये, वह नहीं है और न आज तक हुई है ; आज तक उसने बिल्कुल गलत ढंग से विचार किया है। मार खाते खाते जैसे किसी आदमी को अकल आ जाती है वैसे ही उसको एक दम से अकल आई दिखाई देती है और मार खा खा कर ध्यान दिया जाता है, पहले दिया ही नहीं जाता है ।

आप देखें कि सैल्फ रिलायेंस का नारा कब लगाया जाता है। अब जब कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका ने अनाज देने से इन्कार किया तो फूड के मामले में सैल्फ रिलायेंस का नारा लगाया गया । तब जय किसान और जय जवान का नारा लगाया गया । जब तक उसके अन्तर्गत अनाज मिलता रहा तब तक इस तरह का कोई नारा नहीं लगाया गया । अब आर्म्स के बारे में यही नारा लगाया जा रहा है। इसका कारण क्या है? आज दुपहर को पता लगा कि ब्रिटेन ने जो कांट्रेक्ट किया था स्पेयर पार्टस के बारे में, उनको देने

से उसने इन्कार कर दिया है। अमरीका, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान सब हमारे दुश्मन हो गए हैं और जब सरकार ने देखा कि अब कहीं से और किसी के पास से भी हमें आर्म्स नहीं मिलेंगे तब आर्म्स के मामले में भी सैल्फ रिलायेंस का नारा लगाया गया। क्या इससे पहले हमें इस मामले में नहीं सोचना चाहिए था? क्या इससे पहले हमें अपनी नेवल स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं करना चाहिए था। समुद्री रास्ते से आक्रमण होगा तब सरकार इस तरफ ध्यान देगी। जो गलफास होता है, वही गलफास सरकार को समुद्र के रास्ते से भी लग रहा है।

अंदमान में जो मिल हो कर आए है उन्होंने मुझ को बताया है कि वहां जितना चीन की तरफ से प्रोपेगन्डा हो रहा है, भारत की तरफ से नहीं हो रहा है। चीन का सब व्यापार वहां होता है और हमारा जो प्रचार वहां होना चाहिए नहीं हो रहा है। मैं रघुनाथ सिंह जी को भी कहना चाहता हूं जो कि नेवी की तरफ इतना ध्यान दे रहे है और जो मर्चेंट शिपिंग के अध्यक्ष भी हैं कि वे अंदमान की तरफ भी ध्यान दें। उसके आसपास जितने द्वीप हैं उन में भी चीन का ज्यादा इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। और भारत के नीचे आप जायें, सीलोन के आसपास जाए, वहां जितने आइलैंड हैं वहां ब्रिटेन का ज्यादा जोर हो रहा है। जनता को तो वहां जाना ही चाहिए, अपना माल भेजना ही चाहिये लेकिन साथ-साथ शासन का भी लक्ष्य उस ओर होना चाहिये।

डिफेंस मिनिस्टरी की एनुअल रिपोर्ट 1964-65 की मेरे हाथ में है। उस में फ्रिगेट्स के बारे में यह लिखा हुआ है:

"The necessary agreement has been signed with the foreign collaborators and it is anticipated that the Frigate will join the Navy between 1971 and 1973."

1971 और 1973 के पहले क्या होगा? आपको चाहिए कि आत्मनिर्भर बनने की ओर आप कदम उठायें। आपके पास शिपयार्ड हैं, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है वहां यदि नेवी के वास्ते शिप और फ्रिगेट्स किसी भी तरह से तैयार किये जा सकते हों तो आपको तैयार करने की कोशिश करनी चाहिये। जहां से अन्न मिले वहां से अन्न, जहां से हथियार मिलें वहां से हथियार, जहां से आर्म्स मिलें वहां से आर्म्स, जहां से नेवी मिले वहां से नेवी, जितना भी जिस देश से मिले उतना वहां आना चाहिए। आज मैंने सुना कि कुछ सबमैरीन्स भी आ रही हैं। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा लक्षण है। इस लिये नेवी को बढ़ाने का जो गवर्नमेंट का फैसला है वह तो अच्छा है, लेकिन यह भी देखिये कि ट्रेनिंग में कितने लोग जाते हैं:

"Only 7 naval officers were deputed abroad for training courses in specialised and technical fields. Another batch of 11 sailors was sent for submarine training in the U.K."

यू० के० में केवल 11 लोग भेजे गए हैं सबमैरीन के संबंध में ट्रेनिंग लेने के लिए। इस तरह से 7 और 11 इतने लोग भेजे गये हैं। दूसरी जगहों पर जो खर्च किया जाता है उस के मुकाबले में जो नौसेना पर खर्च किया जाता है वह बहुत कम है। इस लिये मैं चाहता हूं कि इस रजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए शासन इस बात की तरफ लक्ष्य करे कि हम नेवी के मामले में आत्म निर्भर हो सकें।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर): श्री रघुनाथ सिंह ने जो संकल्प भारतीय नौसेना को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से उसका आधुनिकरण और विकास करने के लिए सदन में प्रस्तुत किया है, उस का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और साथ ही साथ मैं उन्हें बधाई भी देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय के संबंध में यहां पर संकल्प प्रस्तुत किया है। जब देश के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं उस परिस्थिति में यह

[श्री विश्वनाथ पाण्डेय]

आवश्यक है नौसेना, स्थल सेना और जल सेना का विकास हो और सेना के तीनों अंग शक्तिशाली हो जायें ताकि यदि कोई भी बाहरी शक्ति भारत के ऊपर आंख दौड़ाये तो उसे वे नष्ट कर दें। जब तक देश शक्तिशाली नहीं होगा, जब तक देश प्रतिरक्षा के संबंध में शक्तिशाली नहीं होगा, तब तक देश की रक्षा नहीं हो सकती।

मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा मंत्री इस विषय में बहुत जागरूक हैं। उन्होंने सन् 1965 में प्रतिरक्षा के अनुदान पर वाद-विवाद के समय जो भाषण दिया था उसके शब्दों को मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"When I took over in 1962, even then I felt that the strength of our navy was certainly not adequate for our purposes."

"But certainly now we have come to a stage that we cannot any longer neglect the development of our navy."

उन्होंने जो शब्द कहे थे उनसे मालूम होता है कि वे जागरूक हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ जो रुपया नौसेना के विकास के लिये रक्खा गया है वह बहुत कम है। सन् 1963–64 में जब प्रतिरक्षा के ऊपर 704 करोड़ रु० रक्खे गये तो नौसेना के लिये 27 करोड़ रु० रक्खे गये, सन् 1964–65 में जब प्रतिरक्षा के ऊपर 716 करोड़ रु० रक्खे गये तो नौसना के लिये 23 करोड़ रु० रक्खे गये और सन् 1965–66 में जब 748 करोड़ रु० रक्खे गये प्रतिरक्षा के ऊपर तो नौसना के ऊपर केवल 24 करोड़ रु० रक्खे गये। जब हमारी कुल सीमा 9945 मील है तो भारत की सामुद्रिक सीमा 3500 मील है। यानी लगभग 30 प्रतिशत हमारी सामुद्रिक सीमा है। जब कभी हम जलमार्ग में कमजोर हुए हैं, हिन्दुस्तान के ऊपर हमला हुआ है। पुर्तगाल उस रास्ते से आया, फ्रांस भी उसी रास्ते आया। जब तक आप का अधिकार बे आफ बंगाल पर न होगा, पर्शियन गल्फ पर न होगा, हिन्द महासागर पर नहीं होगा, अरेबियन सी पर नहीं होगा, तब तक आप की सुरक्षा नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से आप वायु सेना को और स्थल सेना को थोड़े समय में सुसज्जित कर सकते हैं उस तरीके से सामुद्रिक सेना को ठीक नहीं कर सकते। इस लिए आवश्यक है कि एक अल्पकालिक योजना बनाई जाये, एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाये और एक मध्यमकालिक योजना बनाई जाये। आप यू बोट्स, सबमैरीन्स और फिगेट्स, डिस्ट्रायर्स, जहां से मिलें, लें। लेकिन जिस तरह से आप नैट विमान कारखाने के अन्दर बनाते हैं उसी तरह से आप इन चीजों के कारखाने भी खोलिये। आप अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ायें, इंजीनियरों को बढ़ायें। इस परिस्थिति में जब कि आप के ऊपर चाइना का आक्रमण और पाकिस्तान का आक्रमण मंडरा रहा है आवश्यक है कि आप अपनी जल शक्ति और नौसेना शक्ति को बढ़ायें।

इन शब्दों के साथ जो संकल्प श्री रघुनाथ सिंह ने रक्खा है, मैं उस का समर्थन करता हूं।

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I was very glad to listen to the speech of Shri Raghunath Singh. It is a very well thought out and very well informed speech, in which he emphasised the necessity for strengthening and modernising our navy. There can be no two opinions about it and almost all Members who have spoken have supported the resolution.

He has gone into the historical details of the ancient traditions and glories of our navy. These are all accepted. But every nation has its day, every nation has its greatness. For historical reasons, unfortunately,

we lost our freedom and so much of the glamour and glory of our navy also was gone. As I have said, we are trying to do our best, with the limited resources at our disposal, technical know-how and man-power to expand, develop and modernise our navy.

Shri Raghunath Singh has gone into the details of the naval strength of the surrounding countries like Pakistan, China and Indonesia (*Interruption*). Perhaps has got good information and it may be that he is correct —I cannot deny that. When compared to the navies of these countries, our navy is comparatively smaller and perhaps weaker. Hon. Members know we have got one *Vikrant*, a couple of cruisers, about six destroyers, a few frigates, a few patrol boats and crafts. This is our naval strength. Last year, our Defence Minister went to USA, U.K. and USSR and conducted negotiations with those governments with the object of getting some more help, some more equipment and some more of these vessels. I am glad to say that our negotiations with USSR have been successful and we will be getting very soon a few naval craft which will be very helpful to us.

Our research laboratories are doing excellent work in Cochin and Bombay. Our metallurgical, chemical and physical laboratories are discovering new methods of preserving and safeguarding ships. That is also a good thing that they are doing. Besides that, technical know-how is also equally important. We are sending our scientists, technicians and others to foreign countries and they are also being trained there. However, ultimately, as some hon. Members have said, self-reliance is very essential. We must stand on our own legs. This is the lesson which we have learnt during the last conflict. With that end in view we are trying to expand and develop our indigenous resources. Even the components of so many crafts we are trying to build and utilise from our own indigenous resources.

Hon. Members seem to be very anxious and nervous about the potential strength of our potential enemies. I would like to say, just briefly, that, after all, victories are not won by navies alone. It is a combined effort. It must be a balanced force of navy, air force and land armies. All these things combined together generally determine the victory or defeat of a nation. If I may just remind the hon. Members, for deciding the fate of a nation there are so many factors that are required. It is not only weapons, equipments and morale. All these factors, of course, play an important and vital part. Apart from these industrial resources, agricultural resources, morale of the armed forces, strategy and tactics of the military generals are all factors that play a very important part in deciding the fate of a nation.

I may quote just one example. During the last war, France with four million troops, a well equipped and first class army, did not last for more than three weeks against Germany because Germany had superior techniques, they had a very co-ordinated effort of the land, air and naval force. It is not the naval battle that will decide a war. It was the land army that decided the fate of France. I can quote another example. When Japan attacked Pearl Harbour, seven midget submarines—they committed suicide—sunk nine battle-ships in a space of two hours. The entire American Pacific Fleet has been sunk or damaged and America took about two years to recover from the shock. That is one point. Again, if you recollect Singapore, the *Prince of Wales* and *Repulse*, which were supposed to be impregnable—that is what they used to say—and unsunkable, they were sunk by a few aeroplanes of the Japanese.

After all, it is not the navy alone that decides the fate of a country. They are also vulnerable to weapons. There are many defensive weapons, like submarines, Torpedo boats, etc., etc., which could destroy big bat-

[Shri D. S. Raju].

tle-ships. As Shri Indrajit Gupta has correctly stated, these are very vulnerable and very expensive weapons. An aircraft carrier is worth many crores of rupees and yet one submarine or one depth charge is enough to destroy some of these very costly and expensive equipments.

I do not deny that we should try to expand and modernise our navy and make it up to date. But it takes a long time. It will take three or four years to build a submarine. What is going to happen in the meanwhile? So, we have to depend on other arms before we develop the navy.

We are expanding our shipyards at Mazagon, Garden Reach and Visakhapatnam. Port facilities are being improved. Every effort is being made within the resources available to develop these things and I hope we will be self-reliant within a short time. I do not know how soon we will be able to do that but our attempt has been in that direction.

Shri Indrajit Gupta: What about the joint Commonwealth exercises?

Dr. D. S. Raju: It is a suggestion which Shri Indrajit Gupta has made.

Shri Indrajit Gupta: Not my suggestion; everybody wants to know what you are doing. You have gone sailing with Pakistani and British ships.

Dr. D. S. Raju: The suggestion will be considered.

Shri Ravindra Varma said that he has read in some papers that Indonesia has sent two submarines for the help of Pakistan. I do not know how far it is correct. We will try to make further enquiries and check it up. It is possible. Everybody knows the intensions of Indonesia, China and Pakistan. They are trying to seize every opportunity to humble India, to humiliate India, to weaken India. So, one need not be surprised if they are sending their submarines or other naval craft to the help of Pakistan. It is possible.

Shrimati Sharda Mukerjee has said that our thinking has been very rigid. Perhaps, it is partly, right. But priorities have got to be given and, as I have said, air force and army have the top priority, because they serve our immediate needs. It takes a long time to develop a strong navy and anything might happen in the meanwhile. So, we cannot wait till the navy is developed. We must concentrate all our resources on most urgently needed things. Air force is very important. If we have got a very powerful air force with all sophisticated aeroplanes we can detroy any invading fleet very easily before they reach our shores. Also, our shore-based artillery guns can destroy them before they land on the shores. All these things are possible. Even if they land on any of our beaches, our land forces can effectively meet them.

We must remember the famous speech of Sir Winston Churchill. He made a very famous speech in which he said: we will fight our enemies on the beaches; we will fight them on the land, on the hills, on the dales and the streets of London. This is what he said. It is this famous speech which inspired the whole British nation and even the European countries to fight the enemy.

I think I have covered all the points. I have no objection to accept the Resolution of Shri Raghunath Singh provided he delete the word "immediate", because we are trying to do what he expects us to do, what he hopes us to do, to develop these things. We accept the Resolution with that proviso.

श्री रघुनाथ सिंह : श्रीमन्, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि प्राइवेट मेम्बर का कम से कम एक रजोल्यूशन स्वीकार किया है । नहीं

तो प्राइवेट मेम्बर के जितने रिजोल्यूशन और बिल आते हैं सब को सरकार इन्कार करती है। इसके साथ साथ में श्री एस० एन० दास जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका आमेंडमेंट बहुत सुन्दर है लेकिन जबकि सरकार मूल प्रस्ताव को स्वीकार कर रही है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना आमेंडमेंट वापस ले लें। मैं श्री देव जी को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कुछ नई नई बातें कहीं। बहन शारदा जी ने भी बहुत अच्छी बातें कहीं कि अभी तक वस्त्रों में भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर सके है, नेवी की बात तो दूर है। इन्द्रजीत जी जानते हैं, वह पाकिस्तान के बार्डर पर रहते हैं, ब्रह्मपुत्र की जो समस्या है, बे आफ बंगाल की जो समस्या है उसका आपको काफी ज्ञान है, लिहाजा आपने भी जो बातें कहीं हैं उन पर हमें विचार करना चाहिए। ज्वाइंट नैवल एक्सरसाइज की जहां तक बात है, जबकि हमारा शत्रु हमारे तरीके को जान लेगा हमारी सारी बात जान लेगा तो हम उससे युद्ध क्या कर सकेंगे। रवीन्द्र वर्मा जी ने कहा कि मैंने कुछ इमैजिनरी फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे . . . .

Shri Ravindra Varma: I did not say "All of them were"; I said. "some", perhaps.

श्री रघुनाथ सिंह : लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके सामने सब नोट कर रहा था, एक घंटे तक वह हमारे पास बैठे थे, मैं नोट कर रहा था।

Shri Ravindra Varma: Perhaps I was aware of the sources.

श्री रघुनाथ सिंह : बड़े जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही। वह एक ऐसी जाति को रेप्रेजेंट करते हैं, जो जन्म जात नाविक सैनिक रही है, महाराष्ट्री लोगों ने चार सौ वर्ष तक भारतीय समुद्र तट की रक्षा की है।

एक सदस्य : आप तो बिल्कुल मिनिस्टर जैसे जवाब दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मेक मी मिनिस्टर।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय जी ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा और मैं उपमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो अमेंडमेंट रखा है, कि इम्मीडिएट शब्द हटा दिया जाय, इसको मैं स्वीकार करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: You are accepting the Resolution with the omission of the word "immediate".

Dr. D. S. Raju: Yes, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: Does Shri Shree Narayan Das press his amendment?

Shri Shree Narayan Das: No Sir; I do not press my amendment.

Mr. Deputy-Speaker: Has he the leave of the House to withdraw his amendment?

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"This House is of opinion that steps be taken to develop and modernise Indian Navy in order to make it effective."

The motion was adopted.

16.48 hrs.

RESOLUTION RE: OIL INDUSTRY

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): Sir, I move:—

"This House is of opinion that in view of the present emergency, the oil industry should be placed in the public sector."

As you know, Sir, we have even before expressed our very clear views on the necessity of developing the oil industry entirely and wholly in the